अर्थव्यवस्था, आर्थिक नीति, कल्याणकारी योजनाएँ एवं सुशासन



हाल ही में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड के शोध का प्रमुख संदेश है कि परिवारों की उपभोग संबंधी अपेक्षाएँ, और कंपनियों की भविष्य के बारे में धारणाएँ, वर्तमान आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करती हैं।

भारत में इस शोध का उपयोग लक्षित सब्सिडी, महँगाई प्रबंधन, बेहतर आर्थिक पूर्वानुमानों और सरकारी नीतियों के प्रभावी संचार के लिए किया जा सकता है।

- **प्रमुख तथ्य एवं आँकड़े -**
  - 81 करोड़+ मुफ्त खाद्यान्न के लाभार्थी - लेख के अनुसार, भारत में 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
  - लेख के अनुसार, लाभार्थियों के अनुमान 13-15 वर्ष पुराने आँकड़ों पर आधारित हैं। इसलिए नए डेटा की आवश्यकता है।
  - क्रय प्रबंधक सूचकांक - परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स या पी एम आई कारोबारी गतिविधियों और कंपनियों की आर्थिक अपेक्षाओं का एक प्रमुख संकेतक है।
- **नोबेल विजेताओं के शोध का महत्व -**

अर्थशास्त्री के प्रमुख विचार और भारत के लिए उपयोग रॉबर्ट ई. हॉल के परिवारों के उपभोग व्यवहार और भविष्य की आय संबंधी अपेक्षाओं पर शोध हैं। इससे भारत को जरूरतमंद परिवारों की पहचान करने और लक्षित कल्याणकारी योजनाएँ बनाने में मदद मिल सकती है।

वर्तमान राजकोषीय संकट की स्थिति को देखते हुए अगर जरूरतमंदों की सूची को सही किया जा सके, तो सरकार को थोड़ी राहत मिल सकती है।

माइकल वुडफोर्ड ने कंपनियों की अपेक्षाओं एवं भविष्य की नीतियों का वर्तमान मूल्य निर्धारण पर प्रभाव बताया है। इससे भारत को महँगाई प्रबंधन, आर्थिक पूर्वानुमान और नीतिगत स्पष्टता मिल सकती है। साथ ही, उन्होंने नीतिगत निर्णय को जनता तक पहुँचाने की बात पर जोर दिया है।

- **केवल डेटा के आधार पर सब्सिडी घटाना उचित नहीं होगा -**

भारत में अनौपचारिक रोजगार, आय की अनिश्चितता और क्षेत्रीय असमानताएँ वास्तविक जरूरतों का आकलन कठिन बनाती हैं। इसलिए डेटा-आधारित लक्ष्यीकरण के साथ सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा के लाभ, मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन आवश्यक है।

इसी प्रकार, नीतिगत संचार केवल प्रचार नहीं होना चाहिए। उसमें परामर्श, जवाबदेही और नागरिकों की चिंताओं का वास्तविक समाधान शामिल होना चाहिए।

भविष्य की आर्थिक अपेक्षाएँ वर्तमान उपभोग, निवेश और मूल्य निर्धारण को प्रभावित करती हैं। हॉल और वुडफोर्ड के शोध से भारत को यह सीख मिलती है कि प्रभावी आर्थिक शासन के लिए अपडेटेड डेटा, लक्षित कल्याणकारी नीतियाँ और विश्वसनीय नीतिगत संचार आवश्यक हैं। इन उपायों से राजकोषीय दक्षता बढ़ाई जा सकती है। लेकिन उनका क्रियान्वयन समावेशिता, पारदर्शिता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।

'द हिंदू' में प्रकाशित संपादकीय पर आधारित। 17/10/26